भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 246

जिसका उत्तर मंगलवार 05 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

भारी उद्योगों का विकास

246. श्री आलोक संजर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सहित देश में विभिन्न उद्योगों अर्थात् हेवी इंजीनियरिंग उपकरणों और मशीन टूल्स ऑटोमोटिव, हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इत्यादि के विकास का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन क्षेत्रों में उक्त अवधि के दौरान विकास लक्ष्यों को हासिल कर पाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में उन्हें अपने संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सहित देश में विभिन्न उद्योगों अर्थात् हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स और मशीन टूल्स, ऑटोमोटिव, हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि के विकास का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्षेत्र	**उप क्षेत्र**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स और मशीन टूल्स सेक्टर	1. मशीन टूल्स	11.72%	22.78%	25.69%
	2. डाइस, मॉड्स एवं प्रेस टूल	2.41%	(-) 1.67%	8.93%
	3. वस्त्र मशीनरी	(-) 5.45%	1.06%	3.75%
	4. प्रिंटिंग मशीनरी	7.41%	(-) 2.90%	(-) 8.57%
	5. अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	7.44%	43.45%	14.86%
	6. प्लास्टिक मशीनरी	8.0%	11.11%	12.50%
	7. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	20.10%	15.44%	2.32%
ऑटोमोटिव सेक्टर	यात्री वाहन	7.23%	9.26%	7.91%
	वाणिज्यिक वाहन	11.51%	4.14%	19.97%
	तिपहिया	1.05%	-4.89%	24.19%
	दुपहिया	3.01%	6.89%	14.83%
हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर		**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
	उत्पादन (₹ करोड़ में)	5.77%	9.91%	10.23%

उपर्युक्त के अलावा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) का ब्यौरा निम्नवत है:

	वित्तीय वर्ष 2015-16	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**2017-18 (दूसरी तिमाही तक)**	**2018-19 (दूसरी तिमाही तक)**
कारोबार (₹ करोड़ में) #	25,091	27,740	27,850	11,523	12,397
वर्ष दर वर्ष कारोबार में वृद्धि (%)	(-) 15%	10.6%	0.4%	लागू नहीं	7.6%

(ख) से (घ): भारी उद्योग विभाग के माध्यम से भारत सरकार ने नबंवर, 2014 में 'भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि' के लिए एक योजना आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास सहायता की कमी, व्यावहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के समावेशन की कमी, साझा इंजीनियरिंग सुविधाओं की कमी, क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक कलस्टर पार्क और परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र की कमी जैसी सामना की जा रही बाधाओं का समाधान करना है, जिसके कारण भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर-प्रतिस्पर्धी हो गया है। इस योजना के अंतर्गत, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और सरकार के सहयोग से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में केपिटल गुड्स विनिर्माण यूनिटों को प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में साझा औद्योगिक एकीकृत अवसंरचा सुविधा (आईआईआईएफ) जैसे मशीन टूल औद्योगिक पार्क और साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) तथा अर्थमूविंग, निर्माण कार्य और खनन मशीनरी के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों (टीएंडसीसी) के सृजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

भारत सरकार ने मई, 2016 में राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की घोषणा की। योजना का उद्देश्य केपिटल गुड्स के सभी उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार को सुगम बनाना, कौशल उपलब्धता को बढ़ाना, अनिवार्य मानकों को सुनिश्चित करना और एमएसएमई की वृद्धि तथा क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। इस नीति से केपिटल गुड्स के लिए विश्वस्तरीय केन्द्र के रूप में भारत का निर्माण के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी।

भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने और आईईईएमए से सहायता के बाद, घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के भावी विकास को बढ़ावा देने और उसकी सहायता करने तथा इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग मिशन योजना 2012-2022 आरंभ की। मिशन योजना में व्यक्त विजन 2022 'इलेक्ट्रिक उपकरण के उत्पादन के लिए भारत को पसंदीदा देश बनाना और निर्यात और आयात में संतुलन बनाकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार तक पहुँचना है। मिशन योजना ने कार्रवाई हेतु पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है:
(i) उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता; (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन; (iii) कौशल विकास; (iv) निर्यात, और (v) अप्रत्यक्ष मांग का रूपांतरण।

प्रत्येक संबंधित क्षेत्र की तुलना में, सरकार और उद्योग सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा कार्यनीतिक और नीतिगत हस्तक्षेपों हेतु विस्तृत सिफारिशें की गई। सरकार द्वारा मिशन योजना की अनेक सिफारिशों का समाधान किया गया।

****